



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1990/आषाढ़ 5, 1912

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1990/ASADHA 5, 1912

इस भाग से निम्न पाँच संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के लिए में  
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation**

रेल मंत्रालय

(रेल वोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1990

सा.का.नि. 600(ग) :—रेल रेट अधिकरण, माधारण  
खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के  
साथ पठित, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की  
धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए और रेल रेट अधिकरण नियम, 1959 को अधि-  
कात करने हुए केन्द्रीय सरकार के पर्व अन्वेषण में, निम्नलिखित  
विनियम बनाता है, अधीन :—

रेल रेट अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 1990

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का  
संक्षिप्त नाम रेल रेट अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 1990  
है।

(2) यह अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रबृत्त  
होंगे।

2. परिभाषाएँ :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ  
में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से रेल अधिनियम, 1989 (1989  
का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “परिविहार” से इन विनियमों का परिविहार अभिप्रेत  
है;

(ग) “आवेदक” से धारा 45 के मध्ये आवेदन करने  
वाला रेल प्रशासन अभिप्रेत है;

(घ) “अध्यक्ष” से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) “संहिता” से मिक्रो प्रक्रिया संहिता, 1908  
(1908 का 5) अभिप्रेत है;

(ज) “परिवादी” के धारा 36 के मध्ये परिवाद करने  
वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "मध्यक्षेत्री" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिकरण की इजाजत से किसी कार्यवाही में मध्यस्थे करने के लिए अनुमति किया गया हो;

(ज) 'सदस्य' से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) 'अभिवचन' से धारा 36 के अधीन कोई परिवाद, धारा 45 के अधीन कोई आवेदन, प्रत्यर्थी द्वारा इसमें से किसी का उत्तर, उत्तर का जवाब, जहाँ किसी अधिकरण द्वापा अनुमति या निवेशित किया गया हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मध्यस्थी द्वारा फाइल किए गए, यथास्थिति, समर्थन के आधार प्रथवा अप्लेस हैं।

(ञ) 'कार्यवाही' से अधिकरण के समक्ष कार्यवाही अभिप्रेत है;

(ट) 'निर्देश' से धारा 39 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकरण को किया गया कोई निर्देश अभिप्रेत है;

(ठ) 'प्रतिनिधि' में लिखित रूप से सम्प्रकृत रूप में प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अन्तर्गत कोई विधि व्यवसायी है;

(ड) 'प्रत्यर्थी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 36 के अधीन किसी परिवाद में या धारा 45 के अधीन किसी आवेदन में पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया है;

(इ) 'सचिव' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय, इन विनियमों के अधीन सम्पै गए कृत्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का जो समय-समय पर अधिकरण द्वारा निवेशित किए जाएं, निर्वहन कर रहा है और इसके अन्तर्गत सहायक सचिव और अधिकरण द्वारा सचिव के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई प्रत्यक्षिकारी भी है;

(ए) 'धारा' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(त) 'अधिकरण' से धारा 33 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया रेल रेट अधिकरण अभिप्रेत है;

(थ) उन शब्दों और पदों के, जो यहाँ प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो ऋमणः उनके इस अधिनियम में हैं;

(द) उन शब्दों और पदों के, जो यहाँ प्रयुक्त हैं और इन विनियमों अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो ऋमणः उनके साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में हैं।

3. मुद्रण कला संबंधी विनिर्देश :—अधिकरण को प्रस्तुत किए गए सभी अभिवचन, शपथ पत्र और अन्तर्वर्ती आवेदन और उनकी प्रतियाँ सफेद पूर्ण आकार के फोलियों कागज पर टाइप की गई होंगी या साफ और स्पष्ट रूप से मुद्रित की गई होंगी, वार्डों तरफ कम से कम 4 इंच चौड़ा हाशिया होगा और दायीं तरफ करीब 2.5 इंच चौड़ा हाशिया होगा और पृथक शीटों साथ में जोड़ दी जाएंगी। टाइप लिपि या मुद्रण कागज के केवल एक तरफ होगा और क्रमिक रूप से संख्यांकित किए गए पैरों में विभाजित होगा। तारीखें, जोड़ और संख्याएँ स्पष्ट रूप से अंकों में वर्णित की जाएंगी :

4. प्रतिनिधि की नियुक्ति :—(1) कार्यवाही का कोई पक्षकार लिखित रूप से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष सभी अवसरों पर उपसंजात होने, कार्य करने और सुने जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

परन्तु ऐसी नियुक्ति केवल उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको नियुक्ति आदेश सचिव के पास फाइल किया जाता है :

परन्तु यह और कि अधिकरण का कोई ऐसा सशस्य, जिसने ऐसे मद्दत के रूप में पद धारण किया है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) कोई ऐसी नियुक्ति अथवा प्रतिनिधि की नियुक्ति के निवन्धन उपर नियुक्त करने वाले पक्षकार द्वारा लिखित रूप से कोई गई प्रोषणा द्वारा प्रतिसंहृत किए जा सकेंगे या उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा प्रतिसंहृत या प्रोजेक्ट तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह सचिव के पास फाइल नहीं करविया जाता है।

(3) सहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 3 के उपबंध जहाँ तक हो सके, प्रतिनिधियों को लागू होंगे।

5. दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण, उपसंजात और कार्य करने वाला ——निम्नलिखित द्वारा किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे, उपसंजात हुआ जा सकेगा अथवा कार्य किया जा सकेगा।

(क) किसी फर्म की दशा में उसके भागीदार द्वारा;

(ख) किसी नियमित निकाय, संगम अथवा प्राधिकरण की दशा में, यथास्थिति, उसके अध्यक्ष, समाप्ति, प्रबन्धक निदेशक, महाप्रबन्धक अथवा सचिव द्वारा;

(ग) रेल प्रशासन की दशा में उस रेल प्रशासन के महाप्रबन्धक या मुख्य वाणिजिक अधीक्षक या किसी संविधित विभागाध्यक्ष द्वारा; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की दशा में, सरकार के किसी मंत्रिव या किसी मंत्रकृत सचिव या किसी उप सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा और रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की दशा में रेल बोर्ड के

सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव या किसी कार्यपालक निदेशक अधिकारी किसी निदेशक, संयुक्त निदेशक या उप निदेशक द्वारा।

6. सत्यापनः—(1) प्रत्येक अभिवचन अभिवचन के पक्षकार या पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा अथवा अधिकरण के समाधानप्रद रूप में मामले के तथ्यों से सु-परिचित साबित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संबंधित पैराम्भों के प्रति निर्देश से वह विनिर्दिष्ट करेगा जो वह अपने ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है और जो वह प्राप्त की गई और सच होने के लिए विश्वास की गई ज्ञानकारी के आधार पर सत्यापित करता है।

(3) सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें वह तारीख जितको और वह स्थान जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, कथित होगा।

(4) जहां सत्यापन पक्षकार से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है वहां उसका नाम और पता उसके हस्ताक्षर के नीचे दिया जाएगा।

7. प्रस्तुतिः—विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपर्युक्ति के सिवाय, अधिकरण के लिए प्राप्तयित सभी अभिवचन और वस्तावेज, आवेदन और संसूचनाएं अधिकरण के मुख्यालय में सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी अथवा रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएंगी।

8. प्रस्तुत करने के लिए समयः—(1) निवेशित समय के भीतर फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित या निवेशित अभिवचन और अन्य वस्तावेज उस समय के भीतर अधिकरण के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे।

(2) अधिकरण के कार्यालय में प्राप्ति की तारीख को फाइल करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा।

9. सूचना की तारीख और समयः—(1) अधिकरण या सचिव द्वारा जब तक अन्यथा निवेशित नहीं किया गया हो, यथास्थिति, पक्षकारों या साक्षियों को सूचनाओं और समयों की तारीख रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अधिकरण को दिए गए पते पर की जाएगी।

(2) किसी पक्षकार को सूचना की तारीख प्रतिनिधि पर भी की जा सकेगी।

10. कार्यवाही का प्रारंभः—अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 36 के अधीन किसी परिवाद द्वारा या धारा 45 के अधीन किसी आवेदन द्वारा या धारा 39 के अधीन किसी निर्देश द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी।

11. परिवादः—(1) धारा 36 के अधीन कोई परिवाद अधिकरण को संबोधित होगा और लिखित रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा। उसमें परिवादी का नाम

बर्णन और पूरा पता उपबोधित होगा और यदि उस मामले में परिवादी के लिए कोई प्रतिनिधि है तो उसका नाम और पूरा पता भी कथित होगा।

(2) परिवाद में स्पष्ट और अमित रूप में तथ्यों का विवरण, परिवाद के आधार पर, वह अनुतोष या उत्तरार्थ जिसका परिवादी वाला करता है और जहां रेल प्रशासन से अन्यथा किसी व्यक्ति को प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित करना चाहा गया हो वहां उसको अभियोजित करने के लिए आधार भी उपबोधित होंगे।

12. परिवादियों का संयोजनः—(1) कार्यवाही में एक ही हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति उत्तरार्थ में संयोजन कर सकेंगे, जिन दशा में सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां उनके संयुक्त नामों में होंगी।

(2) जहां एक से अधिक परिवादी है, वहां वे परिवाद में परिवादियों में से किसी एक को या उसके प्रतिनिधि को उस व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित करेंगे, जिस पर किसी समन या सूचना की सभी परिवादियों के लिए और उन्होंने और से तारीख की जा सकेगी।

13. प्रत्यर्थीः—(1) जहां कोई परिवाद रेल प्रशासन के विरुद्ध किया गया है, वहां ऐसे रेल प्रशासन का प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

(2) जहां परिवादी के पास वह विश्वास करने का कारण है कि किसी अन्य व्यक्ति पर उत्तर अनुतोष से जो वह चाह रहा है, तात्परक रूप से प्रभाव पड़ने की मंभावना है वहां ऐसे व्यक्ति को भी प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

(3) प्रत्यर्थी का नाम, बर्णन और पता परिवाद में दिया जाएगा और जहां सरकारी रेल का कोई रेल प्रशासन प्रत्यर्थी है वहां संहिता की धारा 79 के उपर्युक्त लागू होंगे।

14. परिवाद की प्रतियाः—प्रत्येक परिवाद के साथ उतने से दुगुनी प्रतियां होंगी जिनमें पक्षकार हैं और तीन अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के उपर्युक्त के लिए होंगी।

15. फीस और जमाः—प्रत्येक परिवाद के साथ परिवादी 250 रुपए का संशय करेगा और अनन्तिम रूप से 150 रुपए सूचनाओं की तारीख और अन्य प्रक्रियाओं और अभिलेख-नुस्खिका के तैयार करने की लागत के प्रभारों को पूरा करने के लिए जमा करेगा।

16. परिवाद की संवीकारी और रजिस्ट्रीफर्मः—(1) किसी परिवाद की प्राप्ति पर सचिव उत पर उसकी प्राप्ति की तारीख चिन्हित करेगा और उत पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात् वह उत पर यह लिंगोट पूष्टिकृत करेगा कि प्रथम दृष्टया परिवाद अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है अथवा नहीं।

(2) जहां सचिव पृष्ठाक्रित करता है कि परिवाद अधिकरण की अधिकारिता के भीतर नहीं है वहां वह अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा।

(3) जहां कोई परिवाद इन विनियमों के अनुसार नहीं है और उसके साथ आवश्यक फैस या जमा राशि नहीं है और परिवादी सचिव द्वारा अनुभात समय के भीतर लुठि को दूर नहीं करता है, वहां सचिव उसे यथासंभव शीघ्र अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा।

(4) सचिव फाइल किए गए सभी परिवादों को उस क्रम के अनुसार जिसमें वे उसने प्राप्त किए हैं, क्रम संख्याएँ देगा और उन्हे परिशिष्ट-II के प्रस्प-1 में विनिर्दिष्ट किए गए रजिस्टर में बर्ज करेगा।

17. परिवाद का लौटाना :—(1) जहां अधिकरण की राय है कि परिवाद प्रथम दृष्टया उसकी अधिकारिता से पर है वहां वह सचिव को परिवाद को उस आवश्यके पृष्ठकन के साथ लौटाने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) यदि ऐसे पृष्ठाकन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परिवादी अधिकारिता के प्रश्न पर सुने जाने के लिए कोई आवेदन करता है तो अधिकरण परिवादी और ऐसे अन्य पक्षकारों को, जो वह ठीक समझे, सुनने के पश्चात प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

(3) प्रत्यर्थी द्वारा संदत्त की गई फैस का प्रतिदाय कर दिया जाएगा यदि परिवाद उसे विनियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप लौटाया जाता है।

18. पक्षकारों को जोड़ना और निकालना :—(1) अधिकरण, किसी प्रक्रम पर, सचिव की रिपोर्ट या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर, जो अधिकरण को उचित प्रतीत हों, आदेश दे सकेगा कि अनुचित रूप से संयोजित किया गया किसी पक्षकार का नाम, चाहे परिवादी के रूप में या प्रत्यर्थी के रूप में हो, काट दिया जाए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे चाहे परिवादी के रूप में या प्रत्यदर्शी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए, अथवा जिस पर मांगे गए अनुतोष का तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़ सकता हो अथवा अधिकरण के समक्ष जिसके उपर्योजित परिवाद में अंतर्विलित प्रश्नों के न्यायनिर्णयन के लिए उचित या आवश्यक समझी जाए, जोड़ दिया जाए।

परन्तु तथापि कोई भी व्यक्ति परिवादी के रूप में बिना उसकी सहमति के नहीं जोड़ा जाएगा।

(2) कोई कार्यवाही केवल पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विकल नहीं होगी।

(3) जब प्रत्याधियों को जोड़ा जाता है तब परिवाद और रजिस्टर को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और परिवादी अपने परिवाद की अतिरिक्त प्रतियां इतनी

संख्याओं में जितनी जोड़े गए प्रत्याधियों की संख्या के दुगुने के बराबर हो, फाइल करेगा।

19. परिवाद की सूचना का तामील : (1) परिवाद की प्रति प्रत्येक प्रत्यर्थी पर अधिकरण की मुद्रा से मुद्रांकित और सचिव के इस पृष्ठाकन के साथ तामील की जाएगी कि प्रत्यर्थी परिवाद का अपना उत्तर ऐसी तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर फाइल करे और उसमें यह भी कथित होगा कि ऐसे उत्तर को उक्त कालावधि के भीतर फाइल किए जाने में व्यक्तिकर्म की दशा में अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवाद सुनने के लिए अग्रसर हो सकेगा और यह भी कथित होगा कि ऐसे मामले में प्रत्यर्थी को अधिकरण की इजाजत के सिवाय और ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो अधिकरण अधि रोपित करना ठीक समझे, नहीं सुना जाएगा।

(2) किसी रेल प्रशासन की दशा में प्रति की संबंधित रेल के महा प्रबन्धक पर तामील की जा सकती।

(3) जहां अधिकरण की राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वहां एक लोक सूचना भी परिवादी के खर्चों पर और अधिकरण के सचिव द्वारा आदिष्ट रीति से प्रकाशित की जाएगी और उसमें परिवाद फाइल करने पक्षकारों के नाम, अभियोजनों के संक्षिप्त विवरण और चाहे गए अनुतोष का वर्णन होगा तथा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो याचिका में चाहे गए अनुतोष के समर्थन में या उसके विरोध में मध्यक्षेप करने की इच्छा रखता हो, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिकरण को मध्यक्षेप करने की अनुमति देने के लिए आवेदन करने की मध्यक्षा की जाएगी।

(4) यदि यह समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिलेख पर नहीं है किन्तु उनका कार्यवाही में वैसा ही हित है जो परिवादी या प्रत्यर्थी का है तो वह तथ्य लोक सूचना में वर्णित किया जाना चाहिए और ऐसी लोक सूचना के पश्चात अधिकरण द्वारा किया गया कोई विनिश्चय ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगा।

20. परिवाद का वापस लिया जाना : (1) परिवादी परिवाद के सम्बित किए जाने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपने परिवाद को वापस ले सकेगा और उस मामले में अधिकरण खर्चों के बारे में आदेशों सहित ऐसे आवेदन पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) उत्तर फाइल किए जाने के पूर्व परिवाद के वापस लेने की दशा में परिवादी द्वारा संदत की गई फैस का प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

21. परिवाद का समझौता : जब किसी परिवाद का पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा समायोजन किया जाता है तो दोनों पक्षकार सुन्त अधिकरण को उसके बारे में सूचित करेंगे और अधिकरण, ऐसी सूचना के पश्चात

यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, परिवाद का निपटारा करते हुए उपयुक्त आदेश परिन करेगा।

22. उत्तर : (1) उत्तर में उस परिवाद में अन्तर्विष्ट तथ्यों के प्रत्येक अभिकथन की विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार किया जाएगा या उससे इकार किया जाएगा। और ऐसा परिवादी द्वारा अभिकथित आधारों के साधारण इकार द्वारा नहीं किया जाएगा और जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा इकार नहीं किया जाता है उब तक परिवाद में तथ्य के अभिकथन को सामान्यतः प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया समझा जाएगा। उत्तर में उन तात्त्विक तथ्यों का स्पष्ट और प्रभित कथन होगा जिन पर प्रत्यर्थी भरोसा करता है और उसमें प्रतिरक्षा के सभी आधार होंगे।

(2) उत्तर अभिकथन का रूप से संख्याक्रित पैराग्रों में विभाजित होगा और जिस पर हस्ताक्षर किए गए होंगे और वह सम्यक रूप से सत्यापित होगा और उसमें प्रत्यर्थी का नाम, वर्णन और पूरा पता उपर्याप्त होगा और यदि मामले में प्रत्यर्थी के लिए कार्य करने वाला कोई प्रतिनिधि होगा तो उसका नाम और पूरा पता भी अभिकथित होगा।

(3) प्रत्येक उत्तर के साथ जितने पक्षकार हैं उनसे दुगुनी प्रतियाँ होंगी और तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अधिकरण के प्रयोग के लिए होंगी और 150 रुपए की राशि भी सूचना की तामील और अन्य प्रक्रियाओं के प्रभारों तथा अभिलेख प्रस्ताव के तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए जमा की जाएगी।

23. उत्तर की संवेदी और तामील :— (1) किसी उत्तर की प्राप्ति पर सचिव उस पर उसको प्राप्ति की तारीख चिनहित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि उत्तर इन विनियमों के अनुसार नहीं है और उसके साथ आवश्यक जमा राशि नहीं है तथा प्रत्यर्थी सचिव द्वारा अनुशास्त समय के भीतर ब्रुठि में सुधार नहीं करता है तो सचिव उसे यथासभव शीघ्र अधिकरण में समझ आदेशों के लिए रखेंगा।

(3) प्रत्यर्थियों से प्राप्त उत्तरों की प्रतियाँ मुद्रांकित की जाएंगी और सचिव द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उनकी परिवादि पर और ऐसे अन्य पक्षकारों पर, जिसका अधिकरण आदेश दे, तामील की जाएगी।

24. पश्चातवर्ती अभिवचन :— उत्तर के पश्चातवर्ती कोई अभिवचन अधिकरण की इजाजत पर के सिवाय और ऐसे निबन्धनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा किन्तु अधिकरण किसी समय किसी पक्षकार से जबाब या अतिरिक्त जबाब की उसकी उत्तर से दुग्धों प्रतियों के साथ, जितने पक्षकार हैं और अधिकरण के उपयोग के लिए तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ अपेक्षा कर सकेगा और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय नियत कर सकेगा।

25. अभिवचन का संग्रहण :— अधिकरण किसी प्रक्रम पर किसी अभिवचन को संग्रहित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और किसी ऐसे विषय को, जिसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो मामले की उनित सुनवाई को उलझन में डालता है या उसमें विलंब करता है, हठाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवादित प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

26. दस्तावेजों का पेश किया जाना :— (1) जब तक कि अच्छा हेतुक दर्शन नहीं किया जाता है और ऐसे निबन्धनों पर जो अधिकरण ठीक समझे, किसी पक्षकार के कब्जे में के ऐसे सभी दस्तावेज, जिन पर वह सुनवाई में भरोसा करने की इच्छा करता है, उपके द्वारा उतकी सूची महित ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो अधिकरण द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियन्त की जाए, पेश किये जाएंगे। वह उसी समय दस्तावेजों की उतनी प्रतियाँ फाइल करेगा, जितने पक्षकार हैं और तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अधिकरण के प्रयोग के लिए फाइल करेगा।

(2) अधिकरण किसी समयकिसी पक्षकार द्वारा प्रश्नगत मामले से संबंधित उसके कब्जे या शक्ति में के ऐसे दस्तावेज, जो वह ठीक समझे, पेश करने का आदेश दे सकेगा।

27. परिप्रश्न और प्रकटीकरण :— कार्यवाही का कोई पक्षकार अधिकरण को विरोधी पक्षकार को परीक्षा के लिए लिखित रूप में परिप्रश्न परिदृत करने की इजाजत के लिए अथवा विरोधी पक्षकारों को अपने कब्जे में के दस्तावेजों का प्रकटीकरण करने कार्यनिर्देश देने वाले के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और किसी भी दशा में संहिता को प्रथम अनुसूची के आदेश II के उपर्याप्त जहां तक हो सकेगा लागू होंगे और ऐसे आवेदन नामजूर किए जा सके यदि उत्तरों इतना विसंबंध हो जाता है कि जिसमें मामले की सुनवाई का स्थगन करना आवश्यक हो जाए।

28. दस्तावेजों का निरीक्षण :— (1) कोई भी पक्षकार किसी भी समय उस द्वारे पक्षकार को, जिसके अभिवचनों या शपथ पत्रों में किसी दस्तावेज का निरीक्षण किया गया है सूचना देने का हकदार होगा और ऐसी सूचना ऐसा दस्तावेज सूचना देने वाले पक्षकार के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने को आवत और उको प्रतियाँ भेजो की अनुज्ञा देने के लिए होंगी और ऐसी सूचना का अनुपालन नहीं करने वाला पक्षकार पश्चातवर्ती किसी ऐसे दस्तावेज को अपनी ओर से साक्षा में रखने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि वह अतिरिक्त राशि समाधान नहीं कर देता है कि उसके पास ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) अधिकरण के समक्ष चाहे स्वेच्छिक रूप से या अध्यपेक्षा पर, पेश की गई सभी पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं का, पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

परन्तु अधिकरण अपने विवेकानुसार पुस्तकों, दस्तावेजों और वस्तुओं के ऐसे भागों के प्रकाशन से इकार कर सकेगा।

जिन का प्रकाशन पक्षकार अपने हित के प्रतिकूल होने वाले बताएं।

29. विवादियों की विरचना :— (1) अभिवचनों की समाप्ति और दस्तावेजों के फाइल करने के पश्चात् अधिकरण पक्षकारों या प्रतिनिधियों से प्रारूप विवादिक देने की अवैधता करेगा।

(2) तथुपरि अधिकरण विवादियों की विरचना करेगा;

(3) जहाँ अधिकरण की राय है कि विवादिक किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके समक्ष नहीं है, परीक्षा के बिना अधिकार पेश न किए गए कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण के बिना ठीक से विरचित नहीं किया जा सकता है वहाँ वह तत्समयप्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हाजिरी की अधिकार प्रतिवाद कर सकेगा।

30. सुनवाई के पूर्व पक्षकारों की परीक्षा :— अधिकरण परिवाद की सुनवाई के पूर्व निम्नलिखित पर विचार करने के प्रयोजन के लिए पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की परीक्षा कर सकेगा—

- (क) पक्षकारों के बीच विवादित विषयों का सरलीकरण, संक्षेपण या समायोजन;
- (ख) प्रत्येक पक्षकार द्वारा दूसरे के दस्तावेजों को स्वीकार करना या उनसे इंकार करना;
- (ग) साक्षियों की संख्या की सीमा;
- (घ) सुनवाई पर प्रत्रिया'; और
- (ङ) ऐसे अन्य विषय जो परिवाद का शीघ्र निपटारा करने में सहायता कर सकेंगे।

31. विवादियों का संशोधन :—अपना विनिश्चय करने के पूर्व किसी भी समय अधिकरण विवादियों में संशोधन कर सकेगा या ऐसे अतिरिक्त विवादियों की विरचना कर सकेगा जो वह पक्षकारों के बीच विवाददग्धता विषयों का अवधारण करने के लिए ठीक समझ या जो आवश्यक हो और वह किसी भी ऐसे विवादिक को निकाल सकेगा जो उसे गलत रूप से विरचित किया गया प्रतीत हो।

32. मध्यक्षेप :—(1) विनियम 19 के उप-विनियम (3) के अधीन वी गई लोक सूचना पर कोई व्यक्ति उक्त उप विनियम में विहित समय के भीतर परिवाद में चाहे गए अनुतोष के समर्थन में या उसके विरोध में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए अधिकरण को अर्जी दे सकेगा।

(2) मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए अर्जी में प्रस्थापित मध्यक्षेप के आधार, कार्यवाही में अर्जीदार की स्थिति और उसका हित और यह कि वह जाहे गए अनुतोष के समर्थन में है या उसके विरोध में, उपर्याणि होना चाहिए।

(3) यह अधिकरण के विवेक पर होगा कि वह पक्षकारों को जोड़ने से संबंधित विनियम 18 के उप विनियम

(1) के उपबन्धों के आधार पर ऐसी इजाजत दे या उसे नामंजूर कर दे।

(4) यदि इजाजत दे दी जाती है तो अर्जीदार को मध्यक्षेपी के रूप में संयोजित किया जाएगा और उसे उसकी सूचना वी जाएगी तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर वह अपना अभिवचन फाइल करेगा जो, यथा-स्थिति, विनियम 11 के उप विनियम (2) अथवा विनियम 22 के उप विनियम (1) के उपबन्धों के अनुसर होगा। वह उसी समय सूचना की तामीर अन्य कार्यवाहियों के बीच को और अभिवेद्य पुस्तक के तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए 150 रुपए और यदि वह परिवाद के समर्थन में मध्यक्षेप करता है तो 250 रुपए की राशि जमा करेगा। वह अपने अभिवचनों की उत्तो से दुगंती प्रतियां जितने पक्षकार हैं गौर और अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के प्रयोग के लिए फाइल करेगा।

33. सुनवाई की तारीख :—विवादियों के पर्वतिर्धारण के पश्चात् अधिकरण परिवाद की सुनवाई के लिए दिन, समय और स्थान नियत करेगा और उसकी संमूचना संबंधित पक्षकारों को देगा।

34. सुने जाने का अधिकार :—(1) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का कोई पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा सुने जाने का हक्कार होगा।

(2) अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सहायक होने की संभावना है अधिकरण को संवेदित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

35. स्थानीय जांच और रिपोर्ट :—किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें अधिकरण स्थानीय जांच को अपेक्षित और उचित समझता है, कि वह किसी रेल अधिकारी को जो किसी सहायक अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् स्थानीय जांच करने के लिए और उस पर अधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए नियत कर सकता। रिपोर्ट की प्राप्ति के बारे में पक्षकारों को नियत समय के भीतर, रिपोर्ट का निरीक्षण करने के पश्चात् अपने आक्षेप यदि कोई हों, फाइल करने के लिए संसूचित किया जा सकेगा और अधिकरण इन आक्षयों का निपटारा करेगा।

परन्तु वह उक्त समय के भीतर फाइल न किए गए किसी आक्षेप पर विचार करने से इंकार कर सकेगा। रिपोर्ट को उस मामले में साक्ष्य का भाग माना जाएगा। संहिता को प्रथम अनुसूची के आदेश 26 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, ऐसी स्थानीय जांचों और रिपोर्टों को लागू होंगे।

36. कमीशन :—अधिकरण कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा। संहिता के आदेश 26 के उपबन्ध जहाँ तक हो सके, इन विनियमों के अधीन निकाले गए कमीशनों को लागू होंगे।

37. साक्षियों को ममत :—(1) कोई पक्षकार, जो अधिकरण के समक्ष या विनियम 36 के अधीन नियुक्त किए

गए आयुक्त के समक्ष उपसज्जाती के लिए साक्षी को समन करने की इच्छा रखता है, सुनवाई की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिन की हाजिरी अपेक्षित है। सूची में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, वर्णन और पता और यह कि व विशेषज्ञ के स्पष्ट में या अन्यथा साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, वणित होगा और अन्त में की तारीख, यदि कोई हो विनिविट करते हुए मामला और दस्तावेज का वर्णन जिससे उन्हें पहचाना जा सके, होगा। वह ऐसी सूची के साथ उन भौतिकों की जिनके उक्त व्यक्ति यात्रा और अधिकरण के समक्ष हाजिरी के लिए हकदार हैं, कुल रकम, जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता में परिगणित की गई हो, जमा करेगा।

(2) जब कभी अधिकरण यह आवश्यक समझे तो वह स्वप्रेरणा से किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने अथवा उसके कब्जे में के किसी दस्तावेज को पंथ करने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को समन करने के खबरों के बारे में आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा।

(3) साक्षियों को विनियम 9 के उप विनियम (1) के अनुसार नियत समय और स्थान पर हाजिर होने की अथवा दस्तावेज वेण करने की अपेक्षा करने वाली समनों की तामील की जाएगी। यदि कोई साक्षी जिस पर इस प्रकार तामील की गई है या अपेक्षित हाजिर होने में असफल होता है तो उसको संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश, 26 के उपन्धरों का आश्रय लेकर हाजिर कराया जा सकेगा।

38. और साक्ष्य:—अधिकरण सुनवाई के किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार से किसी विवाद पर और साक्ष्य के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

39. प्रारम्भिक विधि प्रश्न:—अधिकरण किसी कार्यवाही के पक्षकारों की सम्पत्ति में या किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अभिवृच्छाओं द्वारा उठाए गए किसी विधि के प्रश्न को सुनवाई के लिए रखे जाने और परिवार की सुनवाई के पूर्व किसी समय निपटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा। यदि अधिकरण की राय में ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय सारभूत रूप से सम्पूर्ण परिवाद का निपटाया करता है तो अधिकरण ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो।

40. सुनवाई:—(1) प्रत्येक परिवाद अधिकरण द्वारा नियत किए गए समय और स्थान पर खुले न्यायालय में सुना जाएगा।

(2) सुनवाई प्रति दिन, जहाँ तक अधिकरण की विवेक-बुद्धि से व्यवहारिक और मुविधाजनक हो आगे चलेगी और उसे किसी पक्षकार की प्रेरणा पर, अधिकरण द्वारा पर्याप्त समझे गए कारणों और ऐसे निबन्धनों पर के सिवाय, जिनके

अन्तर्गत खबरों का संदाय है, जिन्हें अधिकरण ठीक साथे स्थगित नहीं किया जाएगा।

41. उपसंजाति में व्यतिक्रम:—यदि परिवादी सुनवाई के लिए नियत किए गए समय और स्थान पर उपसंजात नहीं होता है तो अधिकरण परिवाद को खारिज कर सकेगा अथवा अपने विवेकानुसार परिवाद का समर्थन करने वाले किसी मध्य श्रेणी की प्रेरणा पर सुनवाई करने के लिए प्रप्रसर हो सकेगा और यदि प्रत्यर्थी उसी प्रकार उपसंजात नहीं होता है तो अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवाद को सुनवाई कर सकेगा और विनिश्चय कर सकेगा यदि सुनवाई की किसी स्थगित तारीख पर पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात नहीं होता है तो अधिकरण यथास्थिति परिवाद को खारिज कर सकेगा अथवा उसका एक पक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा अथवा उनकी अनुपस्थिति में मामले का निपटाया कर सकेगा।

42. पुनः सुनवाई:—(1) जब परिवाद व्यतिक्रम के लिए खारिज किया जाता है किन्तु परिवादी अधिकरण का समाधान कर देता है कि व्यतिक्रम के लिए पर्याप्त हेतुक था तो खारिज का आदेश, विरोधी पक्षकार को सूचना के पश्चात, जहाँ आवश्यक हो, अग्रस्त किया जा सकेगा और परिवाद पर खबरों के बारे में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें अधिकरण ठीक समझे, आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जब कोई एक पक्षीय विनिश्चय निया जाता है किन्तु प्रत्यर्थी अधिकरण का समाधान कर देता है कि सूचना की उप पर सम्यक् रूप से उसे तामील नहीं की गई थी अथवा यह कि उसे सुनवाई में उपसंजात होने में किसी पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो एक पक्षीय विनिश्चय अग्रस्त किया जा सकेगा और मामले पर खबरों के बारे में अथवा अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें अधिकरण ठीक समझे, आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) परिवाद के खारिज करने का आदेश अथवा कोई एक-पक्षीय विनिश्चय अग्रस्त करने के लिए आवेदन यथास्थिति परिवाद के खारिज किए जाने के अथवा एक पक्षीय विनिश्चय अग्रस्त किए जाने के तीस दिन के भोर निया जाए तभी कि अधिकरण पर्याप्त कारणों के लिए विलंब के नियम साफी न दे दे।

43. 1872 के अधिनियम 1 का लागू होना:— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, कार्यवाहियों को लागू होंगे।

परन्तु अधिकरण स्वाविवेक से पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवश्यक साक्ष्य सस्ते रूप से और शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपने उपबंधों में से किसी को शिथिल कर सकेगा।

44. शापथ पत्र (1) किसी परिवाद की सुनवाई पर साक्ष्य शापथ पत्र पर या मौखिक रूप से अथवा भागतः शापथ पत्र और भागतः मौखिक रूप से लिया जा सकता है।

परन्तु यदि कोई भी पक्षकार शपथ पत्र द्वारा किसी गांग पर भरोसा करने का आशय रखता है तो वह सुनवाई के कम से कम 10 दिन पूर्व दूसरे पक्षकार को प्रयोग किए जाने के लिए आशयित शपथ पत्र की एक प्रति परिवर्त्त करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा, जिसमें असफल होने पर उसका प्रयोग अधिकरण की विशेष इजाजत से ही करने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी पक्षकार, प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी शपथ पत्र की किसी प्रति की प्राप्ति के पश्चात् 7 दिन के भीतर दूसरे पक्षकार को प्रति परीक्षा के लिए परिवाद की गुनवाई में पेश किए जाने के लिए अभिसाक्षी से अपेक्षा करने वाली सूचना प्रदत्त करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा और जब तक कि अभिसाक्षी इस प्रकार पेश नहीं किया जाना है, तब तक उसके शपथ पत्र का प्रयोग अधिकरण की विशेष इजाजत से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) अधिकरण पर्याप्त हेतुक से किसी भी समय आदेश दे मिलेगा कि कोई विशिष्ट तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकेगा अथवा यह कि किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई के समय ऐसी शर्तों पर, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझ, पढ़ा जा सकेगा;

परन्तु जहाँ अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई भी पक्षकार प्रति परीक्षा के लिए किसी साक्षी के पेश किए जाने की सद्भावी इच्छा रखता है और यह कि ऐसे साक्षी को पेश किया जा सकता है वहाँ ऐसे साक्षी का साक्षण्य शपथ पत्र द्वारा दिया जाना प्राविकृत करने वाला कोई आदेश लिया नहीं किया जाएगा।

(4) कोई भी शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा जो साक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में समर्थ है सिवाय अन्तर्वर्ती कार्यवाहियों में जिनमें उसके विश्वास के बारे में कथन उसके आधारों महत्व स्वीकार किए जा सकेंगे।

(5) अधिकरण के समझ किसी कार्यवाही में दिए जाने वाले किसी शपथ पत्र के प्रयोग के लिए अध्यक्ष अधिकरण के किसी पदाधिकारी को गणय पत्र के अभिसाक्षी को शपथ दिखाने के लिए सशक्त कर सकेगा।

45. मौखिक साक्ष्य:— किसी साक्षी का मौखिक साक्ष्य अधिकरण के निदेशाधीन अंग्रेजी में खुले न्यायालय में लिया जाएगा और टाइप की हुई प्रति पर अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दिया गया किसी अन्य सदृश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) जब साक्षी द्वारा अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया जाता है तो अधिकरण किसी दुभाषणे को नियुक्त करेगा जो शपथ लेगा या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करेगा कि वह साक्ष्य का अंग्रेजी में सही रूप से अनुवाद करेगा दुभाषण को ऐसी फैस का संदाय किया जाएगा जो अधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए।

46. निर्णय:— (1) अधिकरण साक्ष्य और तथ्य मुनेने तथा उन पर विचार करने के पश्चात्, या तो तत्काल या यथासाध्य शीघ्रता से कि भविष्यवर्ती दिन को अपना विनिष्चय देगा और जब विनिष्चय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाता है तब अधिकरण उस प्रयोग के लिए एक दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों को या प्रतिनिधियों को दी जाएगी।

(2) विनिष्चय पर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और विनिष्चय के प्रमाणी भाग की एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

47. खर्च:— (1) अधिकरण अपने विवेकानुमार किसी पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को पूर्णतः या भागतः कार्यवाहियों के खर्चों का संदाय किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। यह तथ्य कि अधिकरण के पास कार्यवाहियों के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई वर्णन नहीं होगा।

(2) अधिकरण के समझ कार्यवाहियों के लिए और उनके संबंध में खर्चों के अधिनिर्णय के लिए अनुज्ञा फीस का मापमान वह होगा जो परिशिष्ट 1 में दर्शित रिया गया है।

(3) खर्चों का विल सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और अधिकरण के विनिष्चय के साथ संलग्न किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पक्षकारों को भेजो जाएगी। खर्चों के विल में, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार के कथन पर सचिव या अधिकरण द्वारा संशोधन किया जाएगा।

48. अधिकरण के कार्यक्रमों में परिवर्तन:— जहाँ अधिकरण अपने समझ किसी कार्यवाही को समाप्त करने से अपने कार्यक्रमों में किसी परिवर्तन के कारण तित्रिग्राम रहा है वहाँ उत्तरवर्ती पुनर्गठित अधिकरण उसे उस प्रक्रम से पुनः आरंभ कर सकेगा जिस पर पूर्व अधिकरण ने उसे छोड़ा था और वह कोई ऐसा विनिष्ठिय दे सकेगा या तित्रिग्रामिपोट प्रस्तुत कर सकेगा जो उसके पूर्वतीर्ती द्वारा नहीं किया गया है या खिलोई प्रस्तुत नहीं को गई है, और अरां पूर्वतीर्ती द्वारा दिए गए किसी विनिष्चय में वर्णित खर्चों के बिन का संशोधन कर सकेगा।

49. लुटियों का पूर्द्धिकरण:— अधिकरण के किसी विनिष्चय या आदेश में तित्रिकीय या अंकगणितीय गलतियों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें होने वाली लुटियों को या तो स्व-प्ररेणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर अधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

50. अधिकरण किसी भी समय और खर्चों के बारे में या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, अपने समझ किसी कार्यवाही में किसी लुटि या गलती का संशोधन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही में उठाए गए या उस पर आधारित

किसी शासनीयक विवादप्रकल्प का प्रयत्न अवधारण करने के प्रयोजन के लिए नमी अधिकारण मंडीधन दिल जाते हैं।

51. अनावर्णी सादेग - अधिकारण ऐसे अन्वेषनी अधिकारों की जिम्मेदारी अन्वेषनी व्योदय भी है, जो अवश्यक हो, भूत्याइ करने के पश्चात् या प्रकाशीय स्थिति में उन्हें परिन कर सकता, उनमें फोटोग्राफ कर सकता या उन्हें अपासन कर सकता।

52. समय का विस्तारण या अनीवरण - अधिकारण ऐसे विधिनों पर जो मामले के व्याय में अपेक्षित हों, कोई कार्य करने या कोई कार्यवाही करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकता या कम कर सकता है-

परन्तु परिवाद या एकपक्षीय विनियोग को खारिज करने के अवश्य को आपसन करने के लिए आवेदन करने के लिए अवधि तो अनीकृत नहीं किया जाएगा।

53. समय की संगणना - ऐसे सभी मामलों में जिन में दिनों तो एक विशिष्ट सम्बन्ध इन विनियमों द्वारा या गतिव या अधिकारण द्वारा पारित किसी आदेश में विवित की गई है तो उसकी गणना प्रथम दिन का अपवर्जन करके और अन्तिम दिन को मार्मान्तिक करके की जाएगी और यदि अधिकारण का कार्यालय अन्तिम दिन बंद रहता है तो समय वी गणना उस दिन का भी अपवर्जन करने की जाएगी। यदि किसी ऐसे दिन जिस दिन किसी पञ्चकार दाग कोई कार्य किया जाना अपेक्षित है और कार्यालय उस दिन बंद रहता है, तो यह उस दिन किया जा सकता जिस दिन कार्यालय अग्रिमी द्वारा खुलेगा।

54. धारा 45 के अधीन आवेदन - ये विनियम, जहाँ तक ही मक्के, बड़ों मामलों के निष्ठाएँ जाने पर लागू होंगे जहाँ कोई उच्च प्रशासन धारा 45 के अधीन आवेदन है।

55. निर्देश - जांच और रिपोर्ट के लिए अधिकारण का जोई अनिर्देश अधिकारण के सचिव को सम्बोधित किसी पत्र के प्राप्त में होता और रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा। पत्र में प्रत्येक वाकों के माथ-पाथ, निम्ननियन्त्रित का विनियोग होगा।

(क) जान और रिपोर्ट के लिए अधिकारण को निर्देशित मामले के बारे , और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कद्दमे को ऐसी व्यापकाती जिसे ब्रह्म सरकार अधिकारण के समस्य मामले के लिए सुनिश्चित ममता है।

56. जांच की सार्वजनिक सूचना - अधिकारण किसी भी प्रक्रम पर जांच में जापन प्रस्तुत करने या सौंधिक जांच देने के लिए मामले में दिनबद्ध व्यापारियों या व्यापार अंगमों या व्यक्तियों या समर्थ बनाने के लिए उसके संचर में भावधारण तथा जांच के बारे में या किसी कार्यवाही के बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित कर सकता।

57. सार्वजनिक जांच :- अधिकारण के स्वाविषेक पर सार्वजनिक जांच सार्वजनिक अधिभूत्याग व्यापक जांच की जांच और स्वाविषेक पर भी जांच महसूस।

58. जांच की रिपोर्ट:- जांच की रिपोर्ट को द्वितीय सम्बाद की प्रस्तुत की जाती है, और वह सम्बाद यदि नहीं शुक्र ममता है, तो उसे जनता को उपलब्ध करायेगी।

59. जांच आधीग - जांच के प्रयोजनों के लिए अधिकारण ऐसे कमीशन विकाल मकेन और ऐसे मालियों को गमन पर मालियों जो वह आवश्यक समझे।

60. अभिनव धूमिका :- किसी परिवाद या आवेदन में संदर्भित प्रत्येक मामले में अभिवृत्तन, विवाद्यों, अभिनियन्त्रित साथ, गृहीत दस्तावेजों और अभिलेख के ऐसे गांठों की जिनके बारे में विवरित स्थि भी गहरा गया है कि वे अभिलेख पूर्मितका का भाग स्थि हैं, टक्कण की गई अभिनेत्र पूर्मितका तैयार की जाएगी। ऐसे अभिलेख पूर्मितकाओं की उनसी प्रतियां तैयार की जाएंगी, जिननी अधिकारण के मद्दयों और पञ्चकारों के लिए अपेक्षित हों। अभिलेख पूर्मितकाओं के तैयार किए जाने का खर्च ऐसे मामले की बाबत जो अधिकारण के कार्यालय में टक्कित किया जाएगा, 1.75 लाख प्रति पृष्ठ के हिमाय में प्रमाणित किया जाएगा।

61. अधिकारण के कार्यकारण के बारे :- जनिवारों, गवावारों और अन्य सार्वजनिक अवकाश, वे दिनों को स्लोइकर और अव्यक्त छाग किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हैं, अधिकारण के कार्यकारण के बारे पूर्वाह्न 10.30 बजे भी अपग्रह्न 1.30 बजे तक होंगे और अपग्रह्न 2.15 बजे से अपग्रह्न 4.30 बजे तक होंगे और अधिकारण के कार्यालय का गमय पूर्वाह्न 10.00 बजे भी अपग्रह्न 1.30 बजे तक होंगे और अपग्रह्न 2.00 बजे से सार्व 6.00 बजे तक होंगे।

62. मान्त्राद्विक अवकाश और दीर्घिकारण . अधिकारण वैष्म ही मान्त्राद्विक अवकाश और दीर्घिकारण गणना जैसे मद्रास उच्च व्यायालय मानता है :

परन्तु कार्यालय अवकाश के धोगत छुला रहेगा और योग्या सामान्य कामकाज करेगा।

परन्तु यह और कि मात्र इस प्राध्यार पर कि अधिकारण अवकाश के दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, समय का बारे विस्तारण मंजुर नहीं किया जाएगा।

63. दस्तावेजों की वापसी .-(1) साथ में गृहीत दस्तावेजों के कार्यवाहियों के निष्ठाएँ जाने के पश्चात् संबद्ध पञ्चकार की व्यक्तिगत स्थि में परिदलत करके वापस लौटाया जाएगा या उसे रमीदी डाक द्वारा लागत या उसकी अपनी जोखिम और लागत पर पासल द्वारा भेजा जाएगा :

परन्तु साथ में गृहीत किसी दस्तावेज को इससे पहले भी वापस लौटाया जा सकता यदि उसके लिए आवेदन करने

शाला पक्षनार ग्रंथित को मूल नक्ते के विषय पर रखी ।  
प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देता है और ऐसी अधिकारी हीन पर  
मूल प्रति प्रस्तुत करने का वचनबंध करता है ।

(2) जहाँ कोई दस्तावेज़ किसी पक्षकारको उसे परिदृष्ट  
वारके बापस लौटा दी जाती है वहाँ उसे प्राप्त करने वाले  
व्यक्ति द्वारा उसकी एक ग्रन्थीद शी जाएगी ।

(3) साक्ष्य में अभिनीत दस्तावेज़ अभिनेत्र का भाग नहीं  
होगे और वे उप-विनियम (1) में अपवृंधित रीति में क्रमशः  
उनके प्रस्तुत करते बाले पक्षकारों को बापस लौटा दिए जाएंगे ।

64. अभिनेत्र की प्रमाणित प्रतियाँ :— जब तक की  
अधिकरण द्वारा विशेष रूप में अन्यथा आदेश न दिया जाए,  
किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार कार्यवाहियों के अभिनेत्र  
के किसी भाग की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का हकदार  
झोगा । ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ अधिकरण के कार्यालय में  
तैयार की जाएंगी और उनके लिए ऐसी दर पर जिन पर  
मकाम उच्च न्यायालय में प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रभार  
निया जाना है, प्रभार लिया जाएगा ।

65. प्रेषण :— अधिकरण का संदर्भ या उसके पास निक्षिप्त  
मधीं धन तकद रूप में अधिकरण के कार्यालय में  
संदर्भ किया जाएगा या धनादेश द्वारा सचिव, रेंज अधिकरण  
मद्रास के नाम में या रेखांकित डाक आदेश या रेखांकित बैंक

द्वारा यज्ञ व्यापारी, इमिसी इत्यत्र वापस ले लाप से  
प्रेषित किया जाएगा ।

66. निक्षेपों के विरुद्ध प्रतिदाय पा वसूली :— किसी  
मामले की ममानि के पञ्चान्, सचिव प्रत्येक पक्षकार द्वारा  
किए गए निक्षेप में से श्वर्च की गई रकम की संगणना करेगा  
और यथास्थिति, अधिक रकम को उसे वापस लौटा देगा  
या कम रकम की उमसे वसूली करेगा ।

67. प्रलय और रजिस्टर :— नामील की जाने वाली  
मुचनाएँ और अधिकरण के कार्यालय में बनाए गए जैसे शब्द  
रिजिस्टर और ग्रन्थ अभिनेत्र ऐसे होंगे जो परिणिष्ट 2 में  
विविरित हैं ।

68. मद्रास उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम :— मद्रास  
उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों का,  
जहाँ तक वे अधिनियम और इन विनियमों में असंगत नहीं  
हैं, अधिकरण के विशेषानुसार पालन किया जा सकेगा ।

69. न्यायालय की मद्रा :— अधिकरण की मद्रा सचिव  
की अधिकारी में रखी जाएगी ।

[मं. टी. सी. आई./89/216/2]

के. ग्रजगोपालन नायर, महापक्ष सचिव,  
रेल दर अधिकरण

#### परिणाम ।

#### [विनियम 47 (2) देखिए]

अधिकरण के ममम कार्यवाही के संबंध में खर्च देने के लिए फीस का मामामाम

| र. |        |
|----|--------|
|    | 250.00 |
|    | 5.00   |
|    | 3.00   |
|    | 5.00   |
|    | 5.00   |
|    | 5.00   |
|    | 5.00   |
|    | 5.00   |
|    | 5.00   |
|    | 10.00  |
|    | 5.00   |

या वास्तविक रूपों  
शब्दों में जो भी  
अस्तिक हो

घारा 36 के अधीन परिवाद, घारा 45 के प्रधीन आवेदन काल नहीं के लिए या परिवाद के मममेत में प्रधानों के लिए  
वकालतनामा के लिए  
कोई अन्य आवेदन काल करते के लिए  
सूखना, समय की तारीख के लिए  
परिषेन भी तारीख के लिए

अधिकरण के विवरण के बाहर लिए गए शापथ पत्र पाठ्य करने के लिए

आदेश अर्जी के लिए  
अधिकरण न्यायालय के किसी अधिकारी के ममम शापथ-पत्र देने के लिए

#### परिणाम 2

#### प्रस्तुप 1

#### वर्तमा परिवाद रजिस्टर

#### [विनियम 16 (4) देखिए]

| क्रम | परिवाद रजिस्टर         | परिवाद   | प्रत्येक | विषय  | मध्यमें | निर्णय की | निर्णय का | प्रभावी | उच्च न्याय-            | प्रक्रीण |
|------|------------------------|----------|----------|-------|---------|-----------|-----------|---------|------------------------|----------|
| सं.  | की और करण की           | की तारीख | का नाम   | वस्तु | का नाम  | तारीख     | प्रभावी   | भाग     | लय को रिट आवेदन,       |          |
|      | उसकी प्राप्ति की तारीख |          |          |       |         |           |           |         | उच्चकाम यदि रोई        |          |
|      |                        |          |          |       |         |           |           |         | को मंसूबित न्यायालय है |          |
|      |                        |          |          |       |         |           |           |         | करने की को अपील या     |          |
|      |                        |          |          |       |         |           |           |         | नारायण गंगोपाल         |          |
|      |                        |          |          |       |         |           |           |         | नथा                    |          |
|      |                        |          |          |       |         |           |           |         | परिणाम                 |          |

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

## परिणाम 2

## प्रक्रम 2

वर्ष का आवेदन रजिस्टर

[विविधम् 16 (4) और विविधम् 51 देखिए]

|  |                   |                 |                      |   |                      |                    |   |  |                         |      |      |
|--|-------------------|-----------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|---|--|-------------------------|------|------|
| क्रम आवेदन<br>मं. को और<br>उसकी प्राप्ति<br>की तारीख | रजिस्ट्री-<br>करण | आवेदक<br>का नाम | प्रत्यर्थी<br>का नाम | मूल<br>कार्यवाही<br>के प्रति<br>निर्देश | मध्यस्थीपी<br>का नाम | निर्णय<br>की तारीख | निर्णय का<br>प्रभावी भाग<br>प्रभावी भाग<br>को संसूचित<br>करने की<br>तारीख | का प्रभावी भाग<br>प्रभावी भाग<br>के पक्षकारों<br>को है | प्रक्रीर्ण<br>टिप्पणिया |      |      |
| (1)  | (2)               | (3)             | (4)                  | (5)                                     | (6)                  | (7)                | (8)   | (9)  | (10)                    | (11) | (12) |

वर्ष का प्रकार्ण/मध्यस्थीप आवेदन रजिस्टर

(विविधम् 51 देखिए)

## परिणाम 3

## प्रक्रम 3

|          |  |                           |                 |                      |              |
|----------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| क्रम सं. | आवेदन की ओर<br>उसकी प्राप्ति<br>की तारीख | रजिस्ट्री-करण<br>की तारीख | आवेदक<br>का नाम | प्रत्यर्थी<br>का नाम | विषय<br>शब्द |
| (1)      | (2)                                      | (3)                       | (4)             | (5)                  | (6)          |

|                                     |                   |               |                   |   |           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|-----------|
| मूल परिवाद/आवेदन<br>को प्रतिनिर्देश | मध्यस्थीपी का नाम | आदेश की तारीख | आदेश को प्रकुर्ति | आवेदन को पक्षकारों को<br>संसूचित करने की<br>तारीख | टिप्पणिया |
| (7)                                 | (8)               | (9)           | (10)              | (11)  | (12)      |

वर्ष का मिर्देश रजिस्टर

## परिणाम 4

(विविधम् 55 देखिए)

## प्रक्रम 4

|  |                              |                     |                            |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| त्रिमंग. निर्देश को विधिविदान रजिस्ट्री-करण को निर्णय की विषय का<br>ग्राम उमसी प्राप्ति की तारीख | अधिकरण को निर्णय<br>की तारीख | सिफारिश<br>की तारीख | सिरोई भेजने वाली टिप्पणिया |
| (1)  | (2)                          | (3)                 | (4)                        |

परिचय २

(विनियम १८ इंशिय)

प्रत्यक्ष ३

रेल रेट अधिकारी मद्रास के गमध

१७--परिवार म-

बनाम

प्रत्यक्षी

प्रत्यक्षी

सेवा में

ने १८--विनियम १८ के विरुद्ध होने वाले उत्तर परिवार मर्मिन विश्वा है और वह निन दा आपदा प्रतीक होता है कि अधिकारी यो परिवार में आवारी प्रण का अधिनियम दाखले सांत विनियम करने में सबक बनाने के लिए उक्त गमध में आवारी परिवारों के द्वारा मर्मिन विश्वा जाना चाहिए।

अब सुचित विश्वा जाना है कि रेल रेट अधिकारी विनियम, १९५०) के विनियम १८ के प्रधान आपसे यह आवारी की जाती है कि आरोग्य १९-- को आप यह बनाने के लिए हग अधिकारी में गमध उत्तर परिवार मर्मिन टो कि आप इस प्रकार मर्मिन विश्वा जाने के लिए गमध है गा तभी आज नारोड १९--सो में हम्माझर से और १. विरोहित विलेट नेट, मद्रास १०५ मिथि अधिकारी तो गद्वा वगाकर दिया गया।

नाचिप  
रेल रेट अधिकारी

परिणाम ४

प्रगति ५

(विनियम १९ इंशिय)<sup>1</sup>

रेल रेट अधिकारी मद्रास के गमध

१९--का परिवार/प्रावेदन म-

बनाम

परिवारी/प्रावेदक

पर्याप्ती

सेवा में

रेल रेट अधिकारी विनियम १९०० के विनियम १९ (१) के प्रधीन आपसे यह आवारी है कि आप संलग्न परिवार/प्रावेदन की समीक्षा को आरोग्य से ३० दिन के भीतर उन पर आवारा उत्तर--परिवार के आप दात्रित यर्में या आपको सुचित किया जाता है कि उक्त गमध के भीतर सेवा उत्तर के स्वास्थ्य को या में अधिकारी परिवार/प्रावेदन यातारी अनुमियन में सुनाई करने के लिए गमध हो सकता है।

आपका उत्तर और उम्मी प्रतियो स्कृप्ट विस्तर से कागीज के प्रस्तुत किया जाए या उत्तर के रजिस्ट्रेशन टाक ने भेजी जाए। आपको सुवना की नामीन, आदि और अमिलेख युक्त की नैटरों के लिए प्रयोग के रूप में १२० रुपए की राशि अंतिम दिन में जमां करनी होती। यह रकम या तो नकद में या सरोआई से सचिव, रेल रेट अधिकारी, मद्रास का घोषणी होतो अवश्य करने गोल्ड भा आव यैक ड्राइव के अंदर जो प्रधान सीधायक के इक्षियी रेल, मद्रास के पक्ष में होती, भेजनी होती।

आव गरव १९--का में हम्माझर से और १. विलेट नेट, मद्रास १०५ मिथि अधिकारी को मुद्रा लगाकर दिया गया।

मधिव  
रेल रेट अधिकारी

परिणामांक

(परिणाम)

## [विनियम 19 (3) प्रोत्तर (4) इस्तेप]

रेट रेट अधिकरण मंत्रालय के समझ

19—का परिचाद/प्रावेदन म.

परिचादी/प्रावेदक

बनाम

प्रतिक्रिया क्रान्तीया परिचादी/प्रावेदक ने यह परिचाद/प्रावेदक शिया है कि

ग्राह यह विकार किया जाता है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो व्यापक से नहीं हैं, जिन्हें उनका भी उन के प्रत्याहित में बहुत किया है जो कान नहीं। परिचादी/प्रावेदक या प्रत्यक्षी का है;

ग्राह रेट अधिकरण विनियम 19 के उपरिनियम (3) और उपरिनियम (4) के अंतर्वेदन यह तीक्ष्णता दो आता है जिससे यह ऐसा किये अपनि, जो ऐसा करना चाहता है, उस व्यक्ति के प्रकाशन के तीम विद्युत के भौतिक परिचाद/प्रावेदक में आदृ गए अनुचरण के समर्थन या विशेष में ग्राहणी वर्तने या परिचारी प्रावेदक संस्था प्रत्यक्षी के पश्च में जोड़े जाने के लिए अधिकरण की अर्जी देसके, जिसमें प्रत्याहित मंत्रज्ञान के आधार के ओर उन भास्तु में पृथक् विवरण के स्वरूप में जोड़े जाने के लिए गए ग्राह विवरण में अर्जीदार का स्थिति ग्राह विवरण होते हैं।

ऐसा नोट यूक्ता के प्रत्यक्षी प्रत्यक्षी द्वारा शिया गया विवरण में नहीं दर्शिया गया है।

ग्राह यह लार्जेंस को मेरे हस्तान्तर से भाग म 3, विटारिया फिलेट, रोड, मद्रास-103 में दिया। परिचारण की मंद्रा लगावर शिया गया।

राजिका

मुश्ति रेट रेट अधिकरण

परिणाम 3

(परा 8)

## [विनियम 29 (2) इस्तेप]

रेट रेट अधिकरण मंत्रालय के समझ

19—का परिचाद/प्रावेदक ने

परिचादी प्रावेदक

बनाम

प्रत्यक्षी

संघ में,

श्री—परिचादी/प्रावेदक

प्रत्यक्षी /प्रत्यक्षी

परिचारण को उपरोक्त मामले में अधिकारी भी विरक्ता परतो है।

यह मूजना भी जानी है कि शार पारीवारिकों को या उनके पूर्व रेट रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 29(1) के अंतर्वेदन उत्तरीका द्वारा ग्राहण विवाह करते हैं।

और यह मूजना भी दी जानी है कि उत्तरीका परिचाद रेट रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 29 के उपरिनियम (1) योग उपरिनियम (3) के अनुगाम अधिकरण के समझ जिसकी वैदिक विवरण में भारीवारी की विवरण की विवरण की दिया जाता है, यहाँ भी अधिकरण की विवरण को दिया जाता है।

यह आप या आपसे और से आपका काउं प्राविधिक उपरोक्त तरी द्वारा है तो उन मामलों को मूजवाई भी उन दो विविध आपका अनुग्रहण में ही दिया जाएगा।

यह यह लार्जेंस को मेरे हस्तान्तर में आग म 3, विटारिया फिलेट रोड, मद्रास 103 में अधिकरण को गुदा लगावर दिया गया।

नोट

रेट रेट अधिकरण



निपुणता;

(मूल 11)

(विविध 35 देखिए)

जनरल अधिकारी, संसद के समक्ष

1990-जनरल अधिकारी/अधिकारी वं.

परिवारी/अधिकारी

बनाम

प्रत्यक्षी

भाव करने के लिए नियुक्त व्यक्ति।

शिक्षण यह समझा है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय जाति विभिन्न है। अतः प्राप्ति ने जनरल अधिकारी विविध, 1990 के विविध 35 के अनुसार के प्रयोगनार्थ संबंधित पक्षकारों को अधिसूचित करने के पश्चात् ऐसी जाति करने वाले उन पर उन नारीकों को या उनमें पूर्व आनंद विपोट प्रस्तुत करने की श्रेष्ठता की जाती है।

किसी ऐसे मालिक को आपके समक्ष आजिर करने, जिसकी आप परीक्षा करना चाहते हैं या किसी ऐसे वसावेद को पेश करत, जिसका आप निर्णय करना चाहते हैं, के लिए आदेशिका, अधिकारण द्वारा आपके आवेदन पर ही जागी की जाएगी। अधिकारण आपको ग्रंथादेश प्राप्त करने के पश्चात् आपके पास अधिक और अधिक के मंदाग का आवेदन देया।

महाभाज नोर्म्स—को भेरे हम्मालग से भौर मं. 3. विकारिया किंवेट रोड, मद्रास-600105 में प्रविकरण को मुद्रा लिएकर दिया गया।

महिला,  
जनरल अधिकारी,  
म.।

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1990

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 48 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and in supersession of the Railway Rates Tribunal Rules, 1959, read with Section 22 of the General Clauses Act 1897 (10 of 1897) the Railway Rates Tribunal, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

RAILWAY RATES TRIBUNAL (PROCEDURE)  
REGULATIONS, 1990

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Railway Rates Tribunal (Procedure) Regulations, 1990.  
(2) They shall come into force on the date of commencement of the Act.
2. Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires,
  - (a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);
  - (b) 'Appendix' means Appendix to these Regulations;

- (c) 'applicant' means the Railway Administration making application under section 45;
- (d) 'Chairman' means Chairman of the Tribunal;
- (e) 'Code' means the code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);
- (f) 'complainant' means a person making a complaint under Section 36;
- (g) 'intervener' means any person allowed to intervene in a proceeding with the leave of the Tribunal;
- (h) 'Member' means Member of the Tribunal;
- (i) 'pleading' means a complaint under Section 36, an application under Section 45, the answer to any of these by the respondent, a reply to the answer wherever allowed or directed by the Tribunal and includes the grounds of support or objections, as the case may be, filed by an intervener;
- (j) 'proceeding' means proceeding before the Tribunal;
- (k) 'reference' means a reference to the Tribunal by the Central Government under Section 39;
- (l) 'representative' means any person duly authorised in writing and includes a legal practitioner within the meaning of Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

- (m) 'respondent' means any person impleaded as a party in a complaint under Section 36 or in an application under Section 45;
- (n) 'Secretary' means the person who for the time being is discharging the functions assigned under these Regulations and such other functions as may from time to time be directed by the Tribunal and includes an Assistant Secretary and any other officer appointed by the Tribunal to discharge the functions of the Secretary;
- (o) 'section' means a section of the Act;
- (p) 'Tribunal' means the Railway Rates Tribunal constituted by the Central Government under section 33;
- (q) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;
- (r) words and expressions used herein and not defined either in these Regulations or in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897);

**3. Typographical specifications.**—All pleadings, affidavits and interlocutory applications and copies thereof presented to the Tribunal shall be typewritten, or printed fairly and legibly on substantial white foolscap folio paper, with a left hand margin at least 4 cm wide and a right hand margin about 2.5 cm wide, and separate sheets shall be stitched together. The type-script or printing shall be on one side only of the paper, and be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sums and numbers shall be mentioned expressly in figures.

**4. Appointment of Representative.**—(1) A party to the proceeding may appoint, in writing, any person as his representative to appear, act and be heard on all occasions before the Tribunal :

Provided that such appointment shall take effect only from the date on which the appointment order is filed with the Secretary :

Provided further that no Member of the Tribunal who has held office as such member shall be appointed as a representative.

(2) Any such appointment or terms of appointment of representative may be revoked or varied by the party appointing him by a declaration in writing :

Provided that such revocation or variation shall not take effect unless it is filed with the Secretary.

(3) The provisions of Order III of the First Schedule of the Code shall, insofar as may be, apply to the representatives.

**5. Authentication of documents, appearance and acting.**—A document may be signed, appearance made or act done :

- (a) in the case of a firm, by any of its partners;
- (b) in the case of a body corporate, association or authority, by its Chairman, President, Managing Director, General Manager or Secretary, as the case may be;
- (c) in the case of a railway administration, by the General Manager or the Chief Commercial Superintendent or any Head of the Department concerned of that railway administration; and
- (d) in the case of the Central Government, by a Secretary or a Joint Secretary or a Deputy Secretary or an Under Secretary to that Government and in the case of Ministry of Railways (Railway Board) by the Secretary or the Joint Secretary or the Deputy Secretary or an Executive Director or a Director, Joint Director or Deputy Director in the Railway Board.

**6. Verification.**—(1) Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties to the pleading or by some other person proved to the satisfaction of the Tribunal to be acquainted with the facts of the case.

(2) The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies on his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true.

(3) The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed.

(4) Where the verification is by some person other than the party, his name and address shall be given underneath his signature.

**7. Presentation.**—Unless otherwise specially provided, all pleadings and documents, applications and communications intended for the Tribunal shall be presented to the Secretary at the Headquarters of the Tribunal or despatched to him by registered post acknowledgement due.

**8. Time for presentation.**—(1) Pleadings and other documents, required or directed to be filed within a certain time, shall be filed at the Tribunal's office within that time.

(2) The date of receipt at the office of the Tribunal shall be taken as the date of filing.

**9. Service of notice and summons.**—(1) Unless otherwise directed by the Tribunal or the Secretary, notices and summonses to the parties or witnesses as the case may be, shall be served by registered post acknowledgement due to the address furnished to the Tribunal.

(2) A notice to a party may also be served on the representative.

10. Initiation of proceeding.—Every proceeding before the Tribunal shall be initiated by a complaint under section 36 or by an application under section 45 or by a reference under section 39.

11. Complaint.—(1) A complaint under section 36 shall be addressed to the Tribunal and shall be in writing signed and verified. It shall set out the name, description and full address of the complainant and, if there is a representative for the complainant in the matter, his name and full address shall also be stated.

(2) The complaint shall contain a clear and concise statement of facts, the grounds of complaint, the relief or remedy which the complainant claims and, where a person other than a railway administration is sought to be impleaded as a respondent, it shall also set forth the grounds for impleading him.

12. (1) Joinder of complainants.—Two or more persons having the same interest in the proceeding may join in a complaint, in which case all subsequent proceeding shall be in their joint names.

(2) Where there are more complainants than one, they shall nominate in the complaint either one of the complainants or his representatives as the person on whom any summons or notice may be served for and on behalf of all the complainants.

13. Respondent.—(1) Where a complaint is made against a railway administration such railway administration shall be impleaded as the respondent.

(2) Where the complainant has reason to believe that any other person is likely to be materially affected by the relief he is seeking, such person shall also be impleaded as a respondent.

(3) The name, description and address of the respondent shall be given in the complaint and, where a railway administration of the Government railway is the respondent, the provisions of section 79 of the Code shall apply.

14. Copies of complaint.—Every complaint shall be accompanied with twice as many copies as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

15. Fee and deposit.—With each complaint, the complainant shall pay a fee of Rs. 250/- and provisionally deposit of Rs. 150/- to meet the charges of the service of notices and other processes and cost of preparation of paper book.

16. Scrutiny and registration of Complaint.—(1) On receipt of a complaint the Secretary shall mark on it the date of its receipt and initial it, and he shall thereafter endorse on it a report whether prima facie the complaint is or is not within the jurisdiction of the Tribunal.

(2) Where the Secretary endorses that the complaint is not within the jurisdiction of the Tribunal he shall lay his report before the Tribunal for orders.

(3) Where a complaint is not in accordance with these regulations or is not accompanied with the necessary fee or deposit, and the complainant does not rectify the defect within the time allowed by the Secretary, the Secretary shall lay it, as soon as possible, before the Tribunal for orders.

(4) The Secretary shall give to the complaints filed, serial numbers according to the order in which they are received by him and enter them in a register specified in Form I of Appendix II.

17. Return of complaint.—(1) Where the Tribunal is of the opinion that a complaint is prima facie beyond its jurisdiction, it shall direct the Secretary to return the complaint with an endorsement to that effect.

(2) If within 30 days of the receipt of such endorsement, the complainant makes an application to be heard on the question of jurisdiction, the Tribunal shall decide the question after hearing the complainant and such other party as it may consider proper.

(3) The fee paid by the complainant shall be refunded to him if the complaint is returned to him as a result of an order passed under sub-regulation (1).

18. Adding and striking out parties.—(1) The Tribunal may, at any stage, either upon or without the report of the Secretary or the application of either party, and on such terms as may appear to the Tribunal to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as complainant or respondent, be struck out, or that the name of any person who ought to have been joined, whether as complainant or respondent, or who may be materially affected by the relief asked for, or whose presence before the Tribunal is considered proper or necessary for adjudication upon the questions involved in the complaint, be added;

1. Provided however that no person shall be added as a complainant without his consent.

2. No proceeding shall be defeated by reason merely of misjoinder or non-joinder of parties.

3. When respondents are added, the complaint and the register shall be accordingly amended; and the complainant shall also file such number of additional copies of his complaint as is equal to twice the number of respondents added.

19. Service notice of complaint.—(1) A copy of the complaint shall be served on each respondent with the seal of the Tribunal and an endorsement by the Secretary requiring the respondent to file his answer to the complaint within 30 days from the date of service, and also stating that, in default of such answer being filed within the said period, the Tribunal may proceed to hear the complaint in his absence and also stating that in such a case, the respondent will not be heard except by leave of the Tribunal and subject to such terms as the Tribunal may deem fit to impose.

(2) In the case of a railway administration, the copy may be served on the General Manager of the railway concerned.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, a public notice shall also be published, at the cost of the complainant and in the manner ordered by the Secretary of the Tribunal, mentioning the filing of the complaint, names of the parties, brief description of its allegations and relief sought, and calling upon any person wishing to intervene in support of or opposition to the relief sought in the complaint to petition the Tribunal within 30 days of publication of the notice for leave to intervene.

(4) If it is considered that there are persons who are not on the record but have the same interest in the proceeding as the complainant or respondent, that fact should be mentioned in the public notice, and any decision given by the Tribunal after such public notice shall apply to all such persons.

20. Withdrawal of complaint.—(1) The complainant may at any stage after the institution of the complaint withdraw his complaint, and in that case the Tribunal may pass such orders, including orders as to costs, as it may deem fit.

(2) In the case of withdrawal of complaint before the answer is filed, the fee paid by the complainant shall be refunded.

21. Compromise of complaint.—When any complaint is adjusted by a compromise between the parties, both of them shall immediately notify the Tribunal of the same, and the Tribunal shall, after such notice, if any, as it may consider necessary, pass suitable orders disposing of the complaint.

22. Answer.—(1) The answer shall admit or deny specifically each allegation of fact contained in the complaint and not by a general denial of the grounds alleged by the complainant, and, unless denied specifically or by necessary implication, an allegation of fact in the complaint shall normally be taken as admitted by the respondent. The answer shall contain a clear and concise statement of the material facts on which the respondent relies and shall raise all grounds of defence.

(2) The answer shall be divided into paragraphs numbered consecutively and signed and duly verified and it shall set out the name, description and full address of the respondent and, if there be a representative acting for the respondent in the matter, his name and full address shall also be stated.

(3) Every answer shall be accompanied with twice as many copies as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal, and a sum of Rs. 150 shall also be deposited to meet the charges of service of notice and other processes and the cost of preparation of paper book.

23. Scrutiny and service of Answer.—(1) On receipt of an answer, the Secretary shall mark on it the date of its receipt and initial it.

(2) If the answer is not in accordance with these regulations, or is not accompanied with the necessary deposit, and the respondent does not rectify the

defect within the time allowed by the Secretary, the Secretary shall lay it as soon as possible before the Tribunal for orders.

(3) Copies of the answers received from the respondents shall be scaled and initialled by the Secretary and served on the complainant and on such other party as the Tribunal may order.

24. Subsequent pleading.—No pleading subsequent to the answer shall be presented except by the leave of the Tribunal and upon such terms as the Tribunal may deem fit, but the Tribunal may at any time require from any of the parties a reply or additional reply together with twice as many copies thereof as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal and fix a time for presenting the same.

25. Amendment of pleading.—The Tribunal may at any stage allow any pleading to be amended, or order any matter to be struck out which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair hearing of the case, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions at issue between the parties.

26. Production of Documents.—(1) Unless for good cause shown and on such terms as the Tribunal may deem fit, all documents in possession of a party on which he wishes to rely at the hearing shall be produced by him, along with the list thereof, on or before such date as may be fixed by the Tribunal for the purpose. He shall file at the same time, as many copies of the documents as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

(2) The Tribunal may, at any time, order the production by any party of such of the documents in his possession or power relating to the matters in question as it may deem fit.

27. Interrogatories and discovery.—Any party to the proceeding may apply to the Tribunal for leave to deliver interrogatories in writing for examination of the opposite party, or for an order directing the opposite party to make a discovery of the documents in his possession, and in either case the provisions of order XI of the first schedule of the Code as far as may be shall apply and such applications may be rejected if they are so delayed as to necessitate an adjournment of the hearing of the case.

28. Inspection of documents.—(1) Either party shall be entitled at any time to give notice to the other party, in whose pleadings or affidavits reference is made to any document, to produce such document for the inspection of the party giving such notice, and to permit him to take copies thereof and the party not complying with such notice shall not afterwards be at liberty to put any such document in evidence on his behalf, unless he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not complying with such notice.

(2) All books, documents and other things produced before the Tribunal, whether voluntarily or on requisition, may be inspected by the parties.

Provided that Tribunal may in its discretion refuse publication of such parts of the books, documents or things produced as the parties may submit to be prejudicial to their interests to publish.

29. Framing of issues.—(1) After the closure of the pleading and the filing of documents, the Tribunal shall call upon the parties or representatives to furnish the draft issues.

(2) The Tribunal shall thereupon frame the issues.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before it or without the inspection of some documents not produced, it may, subject to any law for the time being in force, compel the attendance of, or the production of any document, by any person.

30. Examination of parties before hearing.—The Tribunal may, before the hearing of the complaint examine the parties or their representatives for the purpose of considering :—

- (a) the simplification, narrowing down or adjustment of matters in issue between the parties;
- (b) the admission or denial by each party of the documents of the others ;
- (c) the limitation of the number of witnesses ;
- (d) the procedure at the hearing ; and
- (e) such other matters as may aid in the speedy disposal of the complaint.

31. Amendment of issues.—At any time before giving its decision, the Tribunal may amend the issues or frame additional issues, as it thinks, fit, or may be necessary, for determining the matters in dispute between the parties, and it may strike out any issue that appears to it to be wrongly framed.

32. Intervener.—(1) On the public notice given under sub-regulation (3) of regulation 19 any person may within the time prescribed in the said sub-regulation petition the Tribunal for leave to intervene in support of or in opposition to the relief sought for in the complaint.

(2) A petition for leave to intervene must set forth the grounds of the proposed intervention, the position and interest of the petitioner in the proceeding, and whether the same is in support of or opposition to the relief sought.

(3) It shall be within the Tribunal's discretion to grant or reject such leave in the light of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 18 relating to addition of parties.

(4) If leave is granted, the petitioner shall be impleaded as intervenor and notified of the same, and, within 7 days of receipt of such notice, he shall file his pleading which shall conform to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 11 or sub-regulation (1) of regulation 22, as the case may be. He shall also deposit at the same time Rs. 150/- to meet the

cost of service of notice, other processes and the cost of preparation of paper book and a sum of Rs. 250 if he intervenes in support of the complainant. He shall file twice as many copies of his pleadings as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

33. Date of hearing.—After the settlement of the issues the Tribunal shall fix a day, time and place for the hearing of the complaint and communicate the same to the parties concerned.

34. Right of audience.—(1) Any party to a proceeding before the Tribunal shall be entitled to be heard either in person or by his representative.

(2) The Tribunal may permit any person likely to be of assistance to address the Tribunal.

35. Local inquiry and report.—In any proceeding in which the Tribunal deems a local inquiry to be requisite or proper, it may appoint any Railway Officer not below the rank of an Assistant Officer to hold a local inquiry after notice to the parties and to report thereon to the Tribunal. The receipt of the report may be communicated to the parties for filing their objections, if any after making an inspection of the report, within the time fixed, and the Tribunal shall dispose of these objections :

Provided that it may refuse to consider, any objections not filed within the said time. The report shall be treated as part of the evidence in the case. The provisions of Order XXVI of the First Schedule to the Code shall apply as far as may be, to such local inquiries and reports.

36. Commission.—The Tribunal may at any stage of the proceeding issue a commission for examination of witnesses. The provisions of Order XXVI of the Code shall apply as far as may be to the commissions issued under this regulation.

37. Summons to witnesses.—(1) A party who desires to summon a witness for appearance before the Tribunal or before a Commissioner appointed under regulation 36, shall at least 30 days before the date of hearing, produce a list of persons whose attendance is required, stating the full name, description and address of each person and whether he is required to give evidence as an expert or otherwise or to produce documents, and, in the last mentioned case, specifying the date, if any, and the description of the documents so as to identify them. He shall with such a list deposit the total amount of the allowances to which the said persons are entitled for travelling and attendance before the Tribunal, calculated in accordance with the Rules of the High Court of Judicature at Madras in its ordinary original civil jurisdiction.

(2) Whenever the Tribunal deems it necessary, it may, of its own motion, summon any person to give evidence, or to produce any document in his possession, and pass necessary orders as to the costs of summoning such person.

(3) Witnesses shall be served with summonses in accordance with sub-regulation (1) or regulation 9 requiring them to attend or to produce a document at the time and place fixed. If a witness so served fails to attend as required, his attendance may be enforced by recourse to the provisions of Order XVI or the first Schedule to the Code.

38. Further evidence.—The Tribunal may, at any stage of the hearing, call for further evidence on any issue from any party.

39. Preliminary questions of law.—The Tribunal, may, with consent of the parties to any proceedings, or on the application of any party, or of its own motion, order any point of law raised by the pleadings to be set down for hearing and to be disposed of at any time before the hearing of the complaint. If, in the opinion of the Tribunal, the decision on such point of law substantially disposes of the whole complaint, the Tribunal may make such order as may seem to it to be just and proper.

40. Hearing.—(1) Every complaint shall be heard in open Court at the time and place fixed by the Tribunal.

(2) The hearing shall proceed from day today as far as in the judgment of the Tribunal may be practicable and convenient, and the same shall not be adjourned at the instance of a party except for reasons considered sufficient by the Tribunal and on such terms, including payment of costs, as the Tribunal may deem fit.

41. Default of appearance.—If the complainant does not appear at the time and place appointed for hearing, the Tribunal may dismiss the complaint or, at its discretion, proceed with the hearing at the instance of an intervener supporting the complaint, and if the respondent does not likewise appear, it may hear and decide the complaint in his absence. If at any adjourned date of the hearing the parties or any of them do not appear, the Tribunal may dismiss the complaint or decide it 'ex parte', as the case may be, or it may dispose of the case in their absence.

42. Re-hearing.—(1) When a complaint is dismissed for default, but the complainant satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for default, the order of dismissal may, after notice to the opposite party, where necessary, be set aside and the complaint proceeded with upon such terms as to costs or otherwise as the Tribunal may deem fit.

(2) When an 'ex parte' decision has been made, but the respondent satisfies the Tribunal that notice was not duly served on him, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing, the 'ex parte' decision may be set aside and the case proceeded with upon such terms as to costs or otherwise as the Tribunal may deem fit.

(3) An application for setting aside an order of dismissal of complaint or an 'ex parte' decision shall be made within 30 days of the dismissal of the complaint or the passing of the 'ex parte' decision, as the case may be, unless the Tribunal condones the delay for adequate reasons.

43. Act 1 of 1872 to apply.—The provisions of the Indian Evidence Act 1972 (1 of 1872) shall as far as may be, apply to the proceedings:

Provided that the Tribunal may in its discretion, without prejudice to the rights of the parties relax any of its provisions, for securing the necessary evidence inexpensively and expeditiously.

44. Affidavit.—(1) The evidence at the hearing of a complaint may be taken either by affidavit or viva voce, or partly by affidavit and partly by viva voce;

Provided that if either party intends to rely on any evidence by affidavit, he shall, at least 10 days before the hearing, deliver or send by registered post to the other party a copy of the affidavit intended to be used, failing which he shall not be allowed to use the same except by special leave of the Tribunal.

(2) Either party may, within 7 days after receipt of a copy of any affidavit intended to be so used, deliver or send, by registered post to the other party, a notice requiring the deponent to be produced at the hearing of the complaint for cross-examination, and unless the deponent is so produced, his affidavit shall not be used except by special leave of the Tribunal.

(3) The Tribunal may at any time for sufficient reason, order that any particular fact may be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the Tribunal deems reasonable :

Provided that where it appears to the Tribunal that either party bona fide desires the production of a witness for cross-examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorising the evidence of such witness to be given by affidavit.

(4) An affidavit shall be confined to such facts as the witness is able of his own knowledge to prove, except in interlocutory proceedings, in which statements as to his belief with the grounds thereof may be admitted.

(5) For the purpose of any affidavit to be sworn in any proceeding before the Tribunal, the Chairman may empower any official of the Tribunal to administer an oath to the deponent of the affidavit.

45. Oral evidence.—(1) The oral evidence of a witness shall be taken down in the open court in English under the direction of the Tribunal and the typewritten copy shall be initialled by the Chairman or by any Member of the Tribunal.

(2) When evidence is given by a witness in a language other than English, the Tribunal may appoint an interpreter who shall take oath or solemnly affirm that he will render the evidence into English correctly. The interpreter shall be paid such fees as may be directed by the Tribunal.

46. Judgment.—(1) The Tribunal after hearing and considering the evidence and arguments shall, give its decision, either at once or as soon thereafter

as may be practicable on some future day; and when the decision is to be pronounced on some future day, the Tribunal shall fix a day for that purpose, of which due notice shall be given to the parties or the representatives.

(2) The decision shall be signed by the Chairman and the Members of the Tribunal, and a copy of the operative part of the decision shall be made available to each party.

47. Costs.—(1) The Tribunal may in its discretion order payment of costs of the proceedings by either party to any other, either in whole or in part. The fact that the Tribunal has no jurisdiction in respect of the proceedings shall be no bar to the exercise of such powers.

(2) The scale of fees admissible for the award of costs for and in connection with the proceeding before the Tribunal shall be as shown in the Appendix I.

(3) The bill of costs shall be prepared by the Secretary and attached to the decision of the Tribunal, and a copy thereof shall be sent to the parties. The bill of costs may be corrected by the Secretary or the Tribunal at the instance of any party, if it be necessary to do so.

48. Change in Personnel of Tribunal.—Where the Tribunal is prevented by a change in its personnel from concluding any proceedings before it the succeeding re-constituted Tribunal may resume the same from the stage at which the previous Tribunal left it, and it may give a decision, or submit a report, written but not given or submitted by its predecessor, and correct the bill of costs relating to a decision given by its predecessor.

49. Rectification of errors.—Clerical or arithmetical mistakes in any decision or order of the Tribunal, or errors arising therein from any accidental slip or omission, may at any time be corrected by the Tribunal either of its own motion or on the application of any of the parties.

50. The Tribunal may at any time, and on such terms as to costs or otherwise as it deems fit, amend any defect or error in any proceedings before it and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question at issue raised by or depending on such proceedings.

51. Interlocutory orders.—The Tribunal may pass, vary or set aside, after hearing or 'ex parte' such interlocutory orders, including temporary injunctions, as may be necessary.

52. Enlargement or abridgement of time.—The Tribunal may enlarge or abridge the time limit for doing any act or taking any proceeding upon such terms as the justice of the case may require

Provided that the period prescribed for applying for setting aside an order of dismissal of complaint or an 'ex parte' decision, shall not be abridged.

53. Computation of time.—In all cases in which a particular number of days is prescribed by these regulations or in an order passed by the Secretary or the Tribunal, the same shall be reckoned exclusively of the first day and inclusively of the last day, and if the office of the Tribunal is closed on the last day, the time shall be reckoned exclusively of that day also. If on any day on which an act is required to be done by a party and the office is closed on that day, it may be done on the day on which the office next opens.

54. Application, under Sections.—These regulations shall as far as may be, apply to the disposal of cases where a railway administration is an applicant under section 45.

55. Reference.—A reference to the Tribunal for inquiry and report shall be in the form of a letter addressed to the Secretary of the Tribunal and sent by registered post. The letter shall specify, inter alia,

- (a) the details of the matter referred to the Tribunal for inquiry and report; and
- (b) all information in the possession of the Central Government which that Government may think relevant to the matter before the Tribunal.

56. Public notification of inquiry.—The Tribunal may, at any stage, publish a notification, either generally about the inquiry or about any of the proceeding in connection therewith, to enable the trades or trade associations or persons interested in the matter to submit their memoranda or offer oral evidence at the inquiry.

57. Public inquiry.—At the discretion of the Tribunal, a public inquiry may be held at a time and place announced by public notification.

58. Report of the inquiry.—The report of the inquiry shall be submitted to the Central Government, and that Government may, if it thinks fit, release it to the public.

59. Commissions for inquiry.—For purposes of inquiry, the Tribunal may issue such commissions and summon such witnesses as it may consider necessary.

60. Paper books.—In every case relating to a complaint or an application there shall be prepared typed paper books of the pleadings, issues, evidence recorded, documents admitted and such other parts of the record as may be specifically ordered to form part of the paper book. As many copies of such paper books shall be prepared as may be required for the Members of the Tribunal and the parties. Cost of preparation of paper books shall be charged at Rs. 1.75 per page in respect of such matter as may be typed in the office of the Tribunal.

61. Working hours of the Tribunal.—Except on Saturdays, Sundays and other Public holidays and subject to any order made by the Chairman, the working hours of the Tribunal shall be from 10.30 AM to 1.30 PM and 2.15 PM to 4.30 PM and that of the office of the Tribunal shall be from 10.00 AM to 1.30 PM and 2.00 PM to 6.00 PM.

62. Holidays and Vacations.—The Tribunal may observe the same holidays and vacations as that of the Madras High Court :

Provided that the office shall remain open during the vacation and transact its normal business :

Provided further that no extension of time shall be granted merely on the ground that the Tribunal was closed for vacation.

63. Return of documents (1) Documents admitted in evidence may after the disposal of the proceedings be returned to the party concerned either by being delivered to him in person or sent to him by registered post acknowledgement due, or by parcel at his risk and cost :

Provided that a document admitted in evidence may be returned earlier if the party applying therefore, delivers to the Secretary a

certified copy to be substituted for the original and undertakes to produce the original if required to do so.

(2) Where a document is returned to a party by its being delivered to him, a receipt shall be given by the person receiving it.

(3) Documents not admitted in evidence shall not form a part of the record and shall be returned to the parties respectively producing them in the manner provided in sub-regulation (1).

64. Certified copies of record.—Unless specially ordered otherwise by the Tribunal, a party to a proceeding shall be entitled to have certified copies of any part of the record of the proceeding. Such certified copies shall be prepared in the office of the Tribunal and charged at the rate at which certified copies are charged in the Madras High Court.

65. Remittance.—All monies to be paid to or deposited with the Tribunal shall be paid in cash at the office of the Tribunal or remitted by money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

66. Refund or recovery against deposit.—After the conclusion of a case, the Secretary shall calculate the amount spent out of the deposit made by each party and either return to him the excess or recover from him the deficit, as the case may be.

67. Forms and registers.—The notices to be served and registers and other records to be maintained in the Office of the Tribunal shall be as specified in Appendix II.

68. Rules of practice of Madras High Court.—The rules of practice of the Madras High Court, in so far as they are not inconsistent with the Act and these regulations, may in the discretion of the Tribunal be followed.

69. Court seal.—The seal of the Tribunal shall be kept in the custody of the Secretary.

[No. TC-I/89/216/2]

K. RAJAGOPALAN, Asstt. Secy.,  
Railway Rates Tribunal

## APPENDIX-I

[See regulation 47(2)]

Scale of fees for award of costs in connection with proceedings before the Tribunal.

|  | Rs.  |
|--|--|
| For filing a complaint under Section 36/an application under Section 45 or for intervening in support of a complaint | 250.00                                     |
| For vakalatnama  | 5.00                                       |
| For filing any other application   | 3.00                                       |
| For service of notice, summons   | 5.00 or the actual cost whichever is more. |
| For service of interrogatories   | 5.00                                       |
| For filing any affidavit made outside the Tribunal   | 5.00                                       |
| For injunction petition  | 10.00                                      |
| For making an affidavit before an Officer of the Tribunal/Court  | 5.00                                       |

## APPENDIX-II

## FORM-I

## REGISTER OF COMPLAINT FOR THE YEAR.....

[See regulation (16) 4]

| Sr. No. | Date of complaint and its receipt | Date of registration | Date of complaint | Name of respondent | Subject matter | Name of intervener |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| (1)     | (2)                               | (3)                  | (4)               | (5)                | (6)            | (7)                |
|         |                                   |                      |                   |                    |                |                    |
|         |                                   |                      |                   |                    |                |                    |

  

| Date of judgement | Operative part of judgement | Date of communication of the operative part to parties | Writ to High Court, Appeal to Supreme Court or if any correction and result | Miscellaneous Application |
|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| (8)               | (9)                         | (10)   | (11)  | (12)                      |
|                   |                             |  |   |                           |
|                   |                             |  |   |                           |

## APPENDIX II

## FORM II

## REGISTER OF APPLICATIONS FOR THE YEAR .....

[See regulation 16(4) and regulation 54]

| Sl. No. | Date of application and its receipt | Date of registration | Name of applicant | Name of Respondent | Cross reference to Original proceedings | Name of intervenor |
|---------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|
| (1)     | (2)                                 | (3)                  | (4)               | (5)                | (6)                                     | (7)                |
| .....   | .....                               | .....                | .....             | .....              | .....                                   | .....              |

| Date of judgement | Operative part of the judgement | Date of communication of operative part to parties | Miscellaneous Application, if any. | Remarks. |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| (8)               | (9)                             | (10)   | (11)                               | (12)     |
| .....             | .....                           | .....  | .....                              | .....    |

APPENDIX-II  
FORM-III

## REGISTER OF MISCELLANEOUS/INTERLOCUTORY APPLICATIONS FOR THE YEAR .....

(See regulation 51)

| Sl. No. | Date of application and its receipt | Date of registration | Name of the applicant | Name of the respondent | Subject matter | Cross references to the Original complaint/ application |
|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| (1)     | (2)                                 | (3)                  | (4)                   | (5)                    | (6)            | (7)   |
| .....   | .....                               | .....                | .....                 | .....                  | .....          | .....   |

| Name of the intervenor | Date of the order | Nature of the order | Date of communication of the order to the parties. | Remarks |
|------------------------|-------------------|---------------------|--|---------|
| (8)                    | (9)               | (10)                | (11)   | (x2)    |
| .....                  | .....             | .....               | .....  | .....   |

**APPENDIX-II**  
**(FORM-IV)**

**REGISTER OF REFERENCES FOR THE YEAR.....**

(See Regulation 55)

| Sl. No. | Particulars of reference and date of its receipt | Date of registration | Subject matter of reference | Date of Report of the Tribunal | Recommendation | Date of despatch of the Report | Remarks |
|---------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------|
| (1)     | (2)  | (3)                  | (4)                         | (5)                            | (6)            | (7)                            | (8)     |

**APPENDIX-II**  
**(FORM-V)**

(See regulation 18)

**BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL  
AT MADRAS****COMPLAINT NO.....OF 19.....****COMPLAINANT***Vs.***RESPONDENT****To**

Whereas ..... has instituted the above complaint against ..... for ..... and whereas it appears proper or necessary that you should be added as a complainant in the said matter in order to enable the Tribunal to adjudicate upon and settle the question involved in the complaint.

Take notice that under Regulation 18 of the Railway Rates Tribunal Regulation 1990, you are required on or before the ..... day of ..... 19 ..... to signify to this Tribunal whether you consent to be so added.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ..... day of ..... 19 ..... at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras 105.

Sd/-  
Secretary,  
Railway Rates Tribunal

**APPENDIX-II**  
**(FORM-VI)**

(See regulation 19)

**BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL  
AT MADRAS****COMPLAINT/APPLICATION NO.....OF 19....****COMPLAINANT/APPLICANT***Vs.***RESPONDENT****TO****RESPONDENT**

Under Regulation 19(1) of the Railway Rates Tribunal Regulations 1990, you are hereby required within 30 days from the date of service upon you of the enclosed complaint/application to put in your answer to the same together with ..... copies and to take notice that in default of such answer being put in within the said time, the Tribunal may proceed to hear the said complaint/application in your absence.

Your answer and the copies thereof may be presented to me at my office at the headquarters or sent to me by Registered post. You should also make a provisional deposit of Rs. 150/- to meet the charges of service of notice, etc. and preparation of paper book. The amount may be remitted either in cash/money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or by means of crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ..... day of ..... 19 ..... at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-105.

Secretary  
Railway Rates Tribunal

APPENDIX-II  
(FORM -VII)

[See regulation 19(3) &amp; (4)]

## BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL

AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....OF 19 .

COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

RESPONDENT

Whereas the complainant/applicant above named has made a complaint/application that.....

And, whereas, it is thought that there are numerous persons who are not on record but have the same interest in the proceedings as the complainant/applicant or respondent above named.

This public notice is, therefore, given under Sub-regulations (3) and (4) of Regulation 19 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, so that any person who so desires may petition the Tribunal within 30 days of the publication of this notice for leave to intervene in support of or opposition to the relief sought in the complaint/application or be added on the side of the complainant/applicant or the respondent, setting forth the grounds of the proposed intervention and the position and the interest of the petitioner in the proceedings on the grounds for being added as a party in the said case.

Any decision given by the Tribunal after such public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19. at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary,  
Railway Rates Tribunal.APPENDIX-II  
(FORM-VIII)

[See regulation 29(2)]

## BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL

AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO. ....OF 19 .

COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

RESPONDENT

To.....

COMPLAINANT/APPLICANT/RESPONDENT/INTERVENER

Whereas the Tribunal has to frame issues in the above case.

Take Notice that you shall file the draft issues in the above complaint under regulation 29(1) of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, on or before.....day of.....19 .

And also take notice that the above complaint will come up for hearing and framing issues before the Tribunal, in accordance with sub-regulations (2) and (3) of regulation 29 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, sitting at .....on the.....day of.....19.....at .....O'clock in the.....noon.

If no appearance is made on your behalf by yourself or your representative, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 . at No. 3 Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary,  
Railway Rates Tribunal.

[See regulation 32(4)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL  
AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....of.....19 .....

COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

RESPONDENT

TO .....INTERVENER

On your application, dated.....under Regulation 32(1) of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, you have been granted leave by the Tribunal to intervene in the above complaint/application (in support of/in opposition) to the relief sought.

Under Regulation 32(4) of the said Regulation, you are hereby required within 7 days of the date of receipt of the enclosed complaint/application, to put in your statement of grounds in support of/in opposition to the relief sought, duly signed and verified, together with .....copies thereof, and to take notice that in default of such statement being put in within the said period, the Tribunal may proceed to hear the said complaint/application in your absence.

Further, you are hereby called upon to make alongwith your statement a provisional deposit of Rs. 150/- with the Tribunal to meet the charges for the service of notice, etc., and cost of preparation of paper book, and, as your intervention is in support of the relief sought, also a fee of Rs. 250/- . The amount may be remitted either in cash/money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or by means of crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 .. at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Sd/-

Secretary  
Railways Rates Tribunal  
Madras.

[See regulation (33)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL  
AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....OF.....19 .....

COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

RESPONDENT

TO .....COMPLAINANT/APPLICANT/RESPONDENT/INTERVENER

Take notice that the above complaint/application will come up for hearing before the Tribunal sitting at.....on the.....day of.....19 , at .....O'Clock in the .....noon, on the issues as already settled in this case.

If no appearance is made on your behalf by yourself or your representative....., alongwith your witnesses, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary  
Railway Rates Tribunal

APPENDIX-II  
(FORM-XI)

[See regulation (35)]

**BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL**

**AT MADRAS**

**COMPLAINT/APPLICATION NO. ....:OF.....19**

**COMPLAINANT/APPLICANT**

*Vs.*

**RESPONDENT**

**TO,**

The person appointed to hold the enquiry.

Whereas the Tribunal deems a local enquiry to be requisite in this case, you are hereby required to hold such enquiry under Regulation 35 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990 after notifying the parties concerned, for the purpose of ..... and to submit your report on or before ..... day of ..... 19 .....

Process to compel the attendance before you of any witness or for the production of any document whom or which you may desire to examine or inspect will be issued by this Tribunal on your application.

The Tribunal will order payment of your remuneration and expenses after it has received your report.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ..... day of ..... 19 , at No. 3 Victoria Crescent, Road, Madras-600105.

Secretary,  
Railway Rates Tribunal,  
Madras.